ए-45011/3/2022-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

## कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को अक्तूबर, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश के अवर्गीकृत भाग को इसके साथ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

(अरूप श्याम चौधुरी)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाष नं. 23095091

प्रति

1. केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्यमंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (ईए) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, (दीपम) के प्रधान निजी सचिव।
11. श्री वी.अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव,मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सीएंडसी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (जी-20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-II)/ओएमआई/क्रिप्टो परिसंपत्तियां और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/संयुक्त सचिव (आईएसडी)/संयुक्त सचिव (निवेश) संयुक्त सचिव (बजट)/संयुक्त सचिव (एफएम)/सभी सलाहकार/सीएएए।
17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
18. गार्ड फाइल- 2022

सं. ए-45011/3/2022-प्रशा. तृतीय
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

***

**विषय: अक्टूबर, 2022 माह के लिए आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर मासिक सारांश।**

**I. महीने के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:**

**बृहद आर्थिक अवलोकन:**

वैश्विक अर्थव्यवस्था तेजी से अशांत और अनिश्चित वातावरण को नेविगेट करना जारी रखती है। वैश्विक विकास में मौजूदा मंदी के बावजूद, खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि के बीच कई अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कई दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कमजोरी के कारण सितंबर में लगातार दूसरे महीने वैश्विक समग्र पीएमआई आउटपुट इंडेक्स सिकुड़ गया, क्योंकि उच्च अनिश्चितता और उच्च ऊर्जा कीमतों ने विश्वास को प्रभावित किया। इन प्रतिकूल घटनाओं ने आईएमएफ को, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2023 की विकास दर के अपने अनुमानों को संशोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था पर अपने दृष्टिकोण को कम करने के लिए प्रेरित किया है।

यूक्रेन संघर्ष और प्रकृति की अनिश्चितताओं से भारत की खाद्य प्रणाली पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के मद्देनजर कुछ खाद्य पदार्थों की घरेलू कीमतें बढ़ी हैं। चालू वर्ष में असामयिक लू की लहरों और दक्षिण-पश्चिम मानसून की कमी से भारत की अनाज की उपलब्धता प्रभावित हुई। हालाँकि, सरकार द्वारा लागू किए गए निर्यात प्रतिबंधों ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की ज़रूरतें पूरी तरह से पूरी हों। इसके अलावा, एनएफएसए और पीएमजीकेएवाई के माध्यम से कुशल सरकारी कार्रवाइयां, एफसीआई के सुव्यवस्थित खरीद और उठाव संचालन द्वारा सक्षम हैं, जिससे अंतिम व्यक्ति तक खाद्य आपूर्ति की पहुंच सुनिश्चित हुई है। भारत की खाद्य सुरक्षा अक्षुण्य बनी हुई है। सितंबर और अक्टूबर में ट्रैक्टर की बिक्री में तेज वृद्धि भी बेहतर भावनाओं और बुवाई क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि की ओर इशारा करती है।

खाद्य आपूर्ति में व्यवधान का प्रभाव मुद्रास्फीति के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। खाद्य मुद्रास्फीति ने समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्ष 2022 के पहले पांच महीनों के दौरान, खाद्य मुद्रास्फीति को तेल और वसा की वैश्विक कीमतों में वृद्धि से आयात किया गया था। जून 2022 से, हालांकि, घरेलू मौसमी कारक खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख स्रोत रहे हैं, जो ज्यादातर सब्जियों, अनाज और उनके उत्पादों की बढ़ी हुई कीमतों में देखे गए हैं। आगे बढ़ते हुए, मौजूदा खुदरा मुद्रास्फीति के दबावों को ताजा खरीफ आवक और उपभोक्ताओं के लिए कम इनपुट लागत के पारगमन के साथ कम होने की उम्मीद है, जिसकी अगली दो तिमाहियों के लिए आरबीआई के मुद्रास्फीति अनुमानों द्वारा भी पुष्टि की गई है।

अक्टूबर 2022 में जारी यूएनडीपी बहु-आयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) का अनुमान है कि पिछले 15 वर्षों के दौरान भारत में 41.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले/उभर गए, गरीबी वर्ष 2005-06 में 55.1 प्रतिशत से घटकर 2019-21 में 16.4 प्रतिशत हो गई। गरीबी कम करने में भारत की सफलता ने भी दक्षिण एशिया में गरीबी कम करने में योगदान दिया है। पहली बार, दक्षिण एशिया, 385 मिलियन गरीब लोगों के साथ, उप-सहारा अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर आ गया है, जहाँ गरीब लोगों की सबसे बड़ी संख्या 579 मिलियन है।

भारत की प्रतिक्रिया और रोकथाम के उपाय, जिसके बाद टीकाकरण का लगभग सार्वभौमीकरण हुआ, को कोविड महामारी को कम करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल आश्चर्य माना गया है।

हालांकि, सफल कोविड प्रबंधन से पहले भी, अन्य सफलता के मामले धीरे-धीरे सामने आ रहे थें, जिनमें शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भी शामिल थी, जिसमें वर्ष 2019 और 2020 के बीच गिरावट आई थी। इसका श्रेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत किए गए रणनीतिक निवेश को दिया जा सकता है।

महामारी के बावजूद, स्कूलों में नामांकन दर में वृद्धि हुई है। सरकारी स्कूलों में नामांकन में भारी वृद्धि ने निजी स्कूलों में दाखिले में गिरावट को पूरा कर दिया है। शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 और 2022-23 में सरकार द्वारा घोषित उपायों से सीखने की बहाली में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।

पीएलएफएस के आंकड़ों के अनुसार जून 2022 को समाप्त होने वाली चौथी तिमाही में शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। ईपीएफओ में निवल पेरोल वृद्धि अगस्त 2022 में दो अंकों की वृद्धि देखी गई है, जो अर्थव्यवस्था के औपचारिककरण में सुधार को दर्शाती है। नौकरी जॉब स्पीक इंडेक्स से पता चलता है कि अधिकांश प्रमुख उद्योगों ने अक्टूबर 2022 के दौरान नियुक्तियों की बढ़त को बनाए रखा। टीम लीज एम्प्लॉयमेंट आउटलुक रिपोर्ट सितंबर में समाप्त होने वाली तिमाही में नियुक्त कार्यकलाप में वृद्धि भी दर्ज करती है, जो भारत में नियुक्ति कार्यकलाप के सूचकांक में वृद्धि के साथ नए व्यावसायिक लाभ में वृद्धि से प्रेरित है।

**2. महत्वपूर्ण विकास:**

(क) गिफ्ट आईएफएससी में विश्व स्तर के विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुरूप, आईएफएससीए (अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसरों और अपतटीय शिक्षा केंद्रों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2022 को 12 अक्टूबर 2022 को अधिसूचित किया गया था।

(ख) आईएफएससीए ने मोरक्को के माराकेच में अक्टूबर 2022 में आईओएससीओ की वार्षिक बैठक में राष्ट्रपतियों की समिति की बैठक के दौरान नए हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया।

(ग) डेटा केंद्र और ऊर्जा संग्रहण प्रणाली को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट में शामिल किया गया है। इसे ई-गजट फा.सं. 13/1/2017-आईएनएफ दिनांक 11.10.2022 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है।

(घ) माननीय वित्त मंत्री ने भारत सरकार द्वारा वहन किए जा रहे ब्याज समतुल्यता (आईईएस) घटक के साथ ऋण सेवा निलंबन की मांग करने वाले 20 उधारकर्ता देशों को जी-20 ऋण सेवा राहत के विस्तार को मंजूरी दी।

(ङ) माननीय वित्त मंत्री की सहमति से, 'सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय व्यवस्था पर रूपरेखा, 2019-2022' की वैधता फिर से 30,2023 जून तक बढ़ा दी गई है, जो 13 नवंबर को समाप्त होने वाली थी।

(च) स्वैप फ्रेमवर्क का विस्तार करने के साथ, माननीय वित्त मंत्री की सहमति से भारतीय रिजर्व बैंक को एसएसए के तहत भूटान को 200 मिलियन अमरीकी डॉलर के समकक्ष भारतीय रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करने के लिए मौजूदा प्रणाली के भीतर 9 महीने की कुल अवधि (प्रत्येक 3 महीनों के अंतराल में 2 बार निकासी का रोल- ओवर) के साथ सूचित किया गया था।

(ii) बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास संस्थाओं के साथ निम्नलिखित ऋण/अनुदान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।

(क) 'हिमालय में जलविद्युत' परियोजना के लिए आर्थिक कार्य विभाग और केएफडब्ल्यू के बीच 80 मिलियन यूरो का ऋण और 1.5 मिलियन यूरो का अनुदान समझौता।

(ख) विश्व बैंक के साथ आईबीआरडी ऋण के लिए 350 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण समझौता गुजरात में रूपांतरित स्वास्थ्य उपलब्धि के लिए प्रणाली सुधार प्रयास (एसआरईएसटीएचएजी) परियोजना।

(iii) परियोजना विस्तार:

दिनांक 11.10.2022 को स्ट्राइव परियोजना के लिए परियोजना समापन तिथि को 18 महीने तक बढ़ाने की सिफारिश भेजी गई थी।

(iv) ऋण/क्रेडिट निरसन:

(क) उत्कृष्टता और इक्विटी के लिए ओडिशा उच्च शिक्षा कार्यक्रम (ऋण संख्या 8782) के लिए दिनांक 21.10.2022 को विश्व बैंक को ऋण राशि से 3.08 मिलियन अमरीकी डालर का निरसन करने का अनुरोध किया गया था।

(ख) 11 अक्टूबर, 2022 को विश्व बैंक को स्ट्राइव परियोजना से 20 मिलियन अमरीकी डालर के निरसन अनुरोध की सिफारिश की गई थी।

(v) ऋण समझौता वार्ता:

दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 को एशियाई विकास बैंक के साथ तमिलनाडु शहरी फ्लैगशिप निवेश प्रोग्राम - प्रोजेक्ट -3 की ऋण समझौता वार्ता हुई। परियोजना की राशि 193.5 मिलियन अमरीकी डालर है।

(vi) इस माह के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) 10 से 14 अक्टूबर 2022 तक आईआईएम शिलांग में आयोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी और अवसंरचना विकास पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

(ख) सार्वजनिक निजी भागीदारी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 17-21 अक्टूबर 2022 तक एजेएनआईएफएम, फरीदाबाद में आयोजित किया गया।

(vii) माननीय वित्त मंत्री ने इस माह के दौरान निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:-

(क) एएस (एमबीसी) की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर, 2022 को आयोजित बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय संस्थाओं से वित्त पोषण की मांग करने वाले प्रस्तावों पर विचार करने के लिए डीईए जांच समिति की 133वीं बैठक हुई।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, जी-20 की 2022 वार्षिक बैठकें, और अन्य संबंधित बैठकों में माननीय वित्त मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 10-16 अक्टूबर, 2022 के दौरान वाशिंगटन डीसी, यूएसए में भाग लिया। आईएमएफ से संबंधित बैठकों में शामिल हैं: i. आईएमएफ ब्रेक फास्ट मीटिंग ii. आईएमएफसी पूर्ण सत्र।

(ग) 10-16 अक्टूबर, 2022 तक वाशिंगटन डीसी में आयोजित विश्व बैंक समूह और आईएमएफ की 2022 वार्षिक बैठकों के दौरान, माननीय वित्त मंत्री ने भारत के लिए विश्व बैंक समूह के गवर्नर के रूप में निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया था:

(घ) 15-अक्टूबर-2022 को विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक।

(ङ) भारत-यूरोपीय संघ निवेश संरक्षण समझौते (आईपीए) का दूसरा दौर 11, 12 और 14 अक्टूबर, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया था।

(च) माननीय वित्त मंत्री ने 12-13 अक्टूबर, 2022 को वाशिंगटन डी.सी., यूएसए में आईएमएफ-डब्ल्यूबी वार्षिक बैठकों की तर्ज पर इंडोनेशियाई जी-20 प्रेसीडेंसी के तहत आयोजित चौथी जी-20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (एफएमसीबीजी) की बैठक में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया।

(छ) एफएमसीबीजी बैठक के दौरान, माननीय विदेश मंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कोरिया, सऊदी अरब, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, मिस्र, ओईसीडी, यूएनडीपी, न्यूजीलैंड, जर्मनी

के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं। यूरोपीय आयोग, संयुक्त अरब अमीरात, आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक (एफडीएमडी) और एफएटीएफ अपनी जी-20 2023 अध्यक्षता के दौरान आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे और भारत की प्राथमिकताओं पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। सचिव (डीईए) ने 2023 में वित्त ट्रैक में भारत की प्राथमिकताओं पर चर्चा करने के लिए कई जी-20 सदस्यों (यूएसए, विश्व बैंक, फ्रांस, श्रीलंका, एफएसबी अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रीका, आईएमएफ एफडीएमडी, कनाडा, एडीबी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग) के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं।

(ज) एएफडीबी (एडीएफ-16) द्वारा क्लाइमेट एक्शन विंडो (सीएडब्ल्यू) पर तकनीकी सत्र।

(viii) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं या उनमें भाग लिया:

(क) सचिव (ईए) और विश्व बैंक की एमडी और सीएफओ सुश्री अंशुला कांत और विश्व बैंक की वीपी और सीआरओ, सुश्री लक्ष्मी श्याम सुंदर के बीच 26-अक्टूबर-2022 को डीईए, नॉर्थ ब्लॉक में एक बैठक आयोजित की गई थी।

(ख) संयुक्त सचिव (एफबी और एडीबी) ने 17-अक्टूबर-2022 को डीईए की ओर से आईडीए दिवस की बैठक में भाग लिया था

(ग) अर्ली वार्निंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) की 31वीं बैठक 6 अक्टूबर 2022 को आयोजित की गई थी। निदेशक (एफएस एण्ड सीएस) समूह के सदस्य हैं और उन्होंने बैठक में भाग लिया।

(घ) एआईआईबी निदेशक मंडल की बैठक वित्त पोषण और निवेश संचालन पर एएलएलबी की परिचालन नीति पर विचार करने के लिए।

(ङ) एनडीबी के वित्तीय मॉडल पर बाजार के विकास के प्रभाव और निहितार्थ पर चर्चा करने के लिए एनडीबी निदेशक मंडल की बैठक।

(च) एनडीबी के वित्तीय मॉडल पर बाजार विकास के प्रभाव और प्रभावों पर चर्चा करने के लिए एनडीबी निदेशक मंडल की बैठक।

**3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन**

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

**4. एसीसी के निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न करना: शून्य**

**5. माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्तावों का विवरण और विभाग में अनुमोदन के लिए प्रतीक्षारत एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:**

| | |
|---|---|
| स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या | : 03 |
| विभाग में स्वीकृति की प्रतीक्षा | : 05 |